

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

समक्ष - एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3018-एक/2015 - विरुद्ध - आदेश  
दिनांक - 30-4-2008 - पारित द्वारा - कलेक्टर जिला  
विदिशा - प्रकरण क्रमांक 175 बी-121/2007-07

वीरेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह  
ग्राम हिरनौदा तहसील बासोदा  
जिला विदिशा मध्य प्रदेश  
विरुद्ध

---आवेदक

1- पप्पू पुत्र रामचरण  
2- रमेश पुत्र तुलाराम  
निवासीगण ग्राम हिरनौदा तहसील बासोदा  
जिला विदिशा मध्य प्रदेश

--अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री टी०सी०नरबरिया)  
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रमोद बाबू श्रीवास्तव)  
(शासन के पैनल लायर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 4-8-2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण  
क्रमांक 175बी-121/2007-07 में पारित आदेश दिनांक  
30-4-2008 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959  
की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि तहसीलदार गँज बासोदा ने  
प्रकरण क्रमांक 69 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक  
30-5-2002 से पप्पू पुत्र रामचरण को ग्राम हिरनौदा स्थित  
भूमि सर्वे क्रमांक 332/1 रकबा 0.836 हैक्टर एवं अनावेदक





रमेश पुत्र तुला को भूमि सर्वे क्रमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर का पट्टा प्रदान किया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा के समक्ष अपील होने पर प्र0क0 29/2002-03 में पारित आदेश दि. 29-8-2003 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर विदिशा के यहाँ निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 5/03-04 में पारित आदेश दि. 13-9-04 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि निगरानी सुनने के अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं है पीढ़ित पक्ष सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।

बीरेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह ने कलेक्टर विदिशा के समक्ष अनियमित भूमि आवंटित करने की शिकायत की, जिसे कलेक्टर विदिशा द्वारा पत्र दि. 23-9-04 से तहसीलदार बासोदा को जॉच हेतु भेजा। तहसीलदार ने जॉच कर अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 175 बी-121/ 2007-07 पेंजीबद्ध किया एवं आदेश दिनांक 30-4-2008 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश जीवित होना अंकित करते हुये प्रकरण समाप्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-9-04 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर स्टेण्ड हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अनावेदक के अभिभाषक द्वारा

प्रस्तुत तर्क पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर ने अधिकारिता न होने के आधार पर निगरानी निरस्त की है एवं विचाराधीन निगरानी कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 175बी-121/2007-07 में पारित आदेश दि. 30-4-2008 के विरुद्ध है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी गँज बासोदा के प्रकरण क्रमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-2003 एवं तहसीलदार गँज बासोदा के प्रकरण क्रमांक 69 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 का संदर्भ दोहराते हुये प्रकरण निरस्त किया है। राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण में समस्त तथ्य समाहित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये समस्त तथ्य खुल चुके हैं जिसके कारण पक्षकारों को न्यायदान के उद्देश्य से विचार कर न्याय प्रदान करना लाजमी है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि तहसीलदार गँज बासोदा ने प्रकरण क्रमांक 69 अ-19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 से पप्पू पुत्र रामचरण को ग्राम हिरनौदा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 332/1 रकबा 0.836 हैक्टर एवं रमेश पुत्र तुला को भूमि सर्वे क्रमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर का पट्टा प्रदान किया है एवं अनुविभागीय अधिकारी गँज बासोदा ने प्रकरण क्रमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-2003 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार के पट्टा आदेश को विधिवत् माना है जबकि अनुविभागीय अधिकारी गँज बासोदा ने तहसीलदार बासोदा के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 16-1-2006 को कलेक्टर विदिशा को अग्रेषित कर बताया है कि रमेश पुत्र तुला





के नाम भूमि आवंटन के पूर्व स्वयं के नाम की भूमि एवं पिता से हिस्से में प्राप्त हो रही भूमि मिलाकर 1.500 हैक्टर से अधिक भूमि है इसका अर्थ यह हुआ कि भूमि आवंटन दिनांक 30-5-2002 को रमेश पुत्र तुलाराम भूमिहीन एवं कृषि श्रमिक नहीं था अपितु बन्टन के पूर्व से ही 1.500 हैक्टर से अधिक भूमि धारण किये था । इस तथ्य के अभिज्ञान में होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के बन्टन आदेश दिनांक 30-5-2002 को पुष्टिकृत करने में भूल की है क्योंकि कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनुविभागीय अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप कमांक 14-7/200/7/2-ए/ दिनांक 2-3-2002 के तारतम्य में रमेश पुत्र तुलाराम का पट्टा हेतु अपात्र होने से पट्टा निरस्ती योग्य है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी गोंज बासोदा का प्रकरण कमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-2003 दोषपूर्ण है जिसके कारण ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही तहसीलदार गोंज बासोदा द्वारा प्रकरण कमांक 69 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 से अनावेदक कमांक 2 रमेश पुत्र तुला को अपात्र होते हुये भी भूमि सर्वे कमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर का पट्टा दिया है जिसके कारण तहसीलदार के आदेश दि 0 30-5-2002 का अंश भाग भी निरस्त किये जाने योग्य हैं

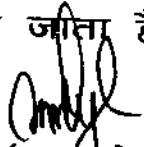
6/ तहसीलदार गोंज बासोदा के प्रतिवेदन दिनांक 15-9-2005 के पद-7 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि अनावेदक कमांक-1 पप्पू के पिता रामचरण के नाम ग्राम हिरनौदा में 1.635 हैक्टर भूमि का खाता है अर्थात् इस पट्टेदार



का परिवार भी भूमिहीन नहीं है जबकि ग्राम में कई कृषि मजदूर (श्रमिक) ऐसे होंगे जिनकी आजीविका का साधन केवल कृषि महजदूरी है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा ने प्रकरण क्रमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-2003 से तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण एवं अपात्र व्यक्ति के हित में जारी बन्टन आदेश दिनांक 30-5-2002 को पुष्टिकृत करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-8-2003 तथा तहसीलदार गॅज बासोदा के आदेश दिनांक 30-5-2002 का पप्पू पुत्र रामचरण के हित में भूमि बंटन का अॅश भाग निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 175बी-121/2007-07 में पारित आदेश दिनांक 30-4-2008, अनुविभागीय अधिकारी गॅज बासोदा के प्रकरण क्रमांक 29/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-2003 तथा तहसीलदार गॅज बासोदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 69 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 से पप्पू पुत्र रामचरण के हित में भूमि सर्वे क्रमांक 332/1 रकबा 0.836 हैक्टर एवं रमेश पुत्र तुला को भूमि सर्वे क्रमांक 332/2 रकबा 0.836 हैक्टर के प्रदत्त पट्टे सम्बन्धी अॅश भाग को निरस्त करते हुये शेष भाग यथावत् रखा जाता है।

R  
1/10

  
(एम0के0सिंह)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर